2

मुख्यमंत्री साय ने किया एरोकॉन 2025 का शुभारंभ

5

राजनीतिक विश्लेषक और प्रखर वक्ता

8

राजेश दुबेः मिजाज से राजा भी और रंक भी

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 18 | प्रति सोमवार, 8 सितंबर 2025 | मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

बेलगाम ज़ुबान और बिगड़ी राजनीतिक समझ का उदाहरण है जीतू पटवारी का विवादित बयान

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार भी अपने कार्यों या किसी सकारात्मक पहल के कारण नहीं, बल्कि अपने ही मुख से निकले बिगड़े स्वर के कारण। राजनीति में नेताओं की जुबान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, किंतु यही जुबान यदि बेलगाम हो जाए तो यह न केवल व्यक्ति की छवि पर चोट करती है, बल्कि पूरी पार्टी को भी भारी नुकसान पहुंचा देती है। हाल ही में पटवारी ने एक ऐसा बयान दे डाला, जिसने प्रदेश की महिलाओं को आहत किया और कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को और भी खिसकाने का काम किया। पटवारी ने प्रदेश की महिलाओं को शराब की आदी बताकर न केवल असंवेदनशीलता दिखाई, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस आज भी अपने ही नेताओं की जुबान पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है।

भाजपा का पलटवार और कांग्रेस की मुश्किलें

पटवारी के इस विवादित बयान को भाजपा ने तुरंत ही मुद्दा बना लिया। भाजपा नेताओं ने न केवल पटवारी को लताड़ लगाई बल्कि कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। भाजपा का यह पलटवार बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पूंजी सत्ता पक्ष की चूक होती है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस बार-बार अपने ही नेताओं के बेतुके और गैर जिम्मेदार बयानों की कीमत क्यों चुकाए? जिस समय कांग्रेस को आक्रामक होकर भाजपा के शासन की विफलताओं पर चोट करनी चाहिए थी, उस समय कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष खुद ही भाजपा को गोल देने का काम कर रहा है।

एनएफएचएस के आंकड़े और पटवारी की गलतबयानी

भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, शराब सेवन में मध्यप्रदेश की महिलाएँ देश भर में 19वें नंबर पर हैं। शीर्ष पर हैं अरुणाचल प्रदेश की 17.8 प्रतिशत महिलाएं, सिक्किम में 14.8 प्रतिशत, असम में 5.5 प्रतिशत, तेलंगाना में 4.9 प्रतिशत, गोवा में 4.8 प्रतिशत, त्रिपुरा में 4.3 प्रतिशत, लद्दाख में 3.6 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 2.8 प्रतिशत और मध्यप्रदेश में 0.4 प्रतिशत महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। हालांकि पटवारी का बयान तथ्यों से परे, बिना किसी आधार के और पूरी तरह से भ्रामक है। प्रदेश की आधी आबादी को शराब की आदी करार दे दे तो यह उसकी राजनीतिक अपरिपक्वता और असंवेदनशीलता का प्रमाण है।

(शेष पेज 6 पर)

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग डेढ़ वर्ष का समय बीत चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संगठन और प्रशासन दोनों मोर्चों पर संतुलन साधते हुए कामकाज आगे बढ़ाया है। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार की हो रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की औपचारिक घोषणा हो सकती है। इससे न केवल सरकार को नई ऊर्जा मिलेगी बल्कि पार्टी संगठन को भी प्रदेश स्तर पर संदेश देने का अवसर मिलेगा। 2023 के अंत में भाजपा की जीत के बाद विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। तब यह माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होगा, लेकिन संगठनात्मक संतुलन और विभिन्न समीकरणों को साधने में समय लगा। अब जाकर लगभग डेढ़ वर्ष बाद मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद शुरू हुई है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और नेताओं में बेचैनी भी।

यह हो सकते हैं संभावित चेहरे

भाजपा सूत्रों के अनुसार, संगठन ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों और जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए मंत्रियों की सूची पर विचार किया है। पार्टी की कोशिश होगी कि आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और शहरी क्षेत्रों से नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए। यह भी कहा जा रहा है कि जिन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में कई नाम चर्चा में हैं, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। (शेष पेज 3 पर)

क्षेत्रवाद और जातीय संतुलन को साधने की होगी कोशिश

मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ की पहल से आकार ले रहा ओबीसी आरक्षण का सपना

-विजया पाठक

सर्वदलीय बैठक में नेताओं ने दिखाया एकमत, कमलनाथ को श्रेय देने का उठा मुद्दा

मध्यप्रदेश की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील और बहुचर्चित रहा है। खासतौर पर ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण का सवाल लंबे समय से राजनीतिक दलों और समाज के केंद्र में बना हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में हुई सर्वदलीय बैठक में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लागू करने पर सहमति बनने के बाद यह उम्मीद मजबूत हो गई है कि जल्द ही प्रदेश में ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार मिलेगा। इस निर्णय के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पहल की रही है, जिन्होंने अपने 18 महीने के कार्यकाल में इस दिशा में ठोस कदम उठाए थे। अपने शुरूआती फैसलों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से प्रभावी रहा। वह जानते थे कि प्रदेश में ओबीसी का बहुत बड़ा तबका रहता है जो किसी न किसी कारण से अपने अधिकारों से वंचित है। (शेष पेज 3 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया एरोकॉन 2025 का शुभारंभ

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हजारों मरीज आज विशेषज्ञ चिकित्सकों के परिश्रम और नवीनतम चिकित्सा पद्धतियों के कारण संजीवनी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते दो दशकों में कैंसर की प्रारंभिक पहचान और उपचार के क्षेत्र में हुए शोध से भविष्य के लिए नई उम्मीदें जगी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में कैंसर डे-केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रदेश में अनेक मरीजों का इलाज संभव हुआ है। जीएसटी में कैंसर की दवाइयों और उपकरणों को सस्ता किए जाने से मरीजों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता का स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में वित्तीय संसाधन कभी बाधा नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में 'एरोकॉन 2025' छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश चैप्टर के दो दिवसीय आयोजन का शुभारंभ कर विशेषज्ञों और उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने

मेडिकल कॉलेज रायपुर के छात्रों के लिए 65 करोड़ रुपये की लागत से नए छात्रावास निर्माण की घोषणा की।

साय ने बताया कि राज्य के अस्पतालों में कैंसर उपचार के लिए अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आज ही एम्स रायपुर में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का शुभारंभ किया जा रहा है, जो यह प्रमाणित करता है कि सरकारी अस्पताल नवीनतम तकनीक अपनाने में अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कैंसर की पहचान में बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही है और राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में इसे तेजी से शामिल कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार लगातार स्वास्थ्य बजट में वृद्धि कर रही है और नये मेडिकल कॉलेज खोल रही है। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में 5,000 बिस्तरों की क्षमता वाली मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है। बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार हर विकल्प पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरगुजा, धरमजयगढ़ और बस्तर में नये अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एरोकॉन 2025 संगोष्ठी कैंसर की रोकथाम और उपचार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एरोकॉन 2025 के सातवें आयोजन में कैंसर उपचार से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक मंच पर आए हैं। इससे इस बीमारी के इलाज में नये आयाम खुलेंगे। उन्होंने कहा कि रायपुर स्थित मेकाहारा अस्पताल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्यभारत के अन्य राज्यों के मरीजों के लिए भी प्रमुख उपचार केंद्र है। भविष्य में अत्याधुनिक तकनीकों और मशीनों के माध्यम से यहां चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, मेडिकल कॉलेज रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी, आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पी.के. पात्रा, विशेषज्ञ चिकित्सकगण, विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

विद्युत विभाग की मनमानी, अव्यवस्थाओं का लगा अंबार

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। गाडरवारा डिवीजन से साइखेड़ा, डोभी, सालिचौका, चीचली सभी जगह से ट्रांसफार्मर लेने किसान जाते हैं परंतु वहां उनको बैठने तक की सुविधा नहीं है। ट्रांसफार्मर लेने जाओ तो पूरा दिन वहां लगता है क्योंकि तुरंत ट्रांसफार्मर न देने की तो एक परंपरा सी बन गई है। बिना किसी नेता या सक्षम अधिकारी के वहां ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता है। सीधा बोल दिया जाता है अभी ट्रांसफार्मर नहीं है। भारतीय किसान संघ ने ज्ञापनों के माध्यम से अनेकों बार मांग की है कि साईखेड़ा से क्षेत्र के लोगों को ट्रांसफार्मर दिलाया जाए। क्या आमजन का हक नहीं है कि वह सुविधा से पानी और बैठने की व्यवस्था प्राप्त कर सके दुर्भाग्य देखिए बिजली का बिल देने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर स्वयं के वाहन से लेकर जाना पड़ता है जबकि यह विभाग की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह ट्रांसफार्मर स्वयं अपने वाहन से लेकर जाए एवं दूसरा लेकर आए परंतु संसाधन की कमी बताते हुए यह सुविधा नहीं दी जाती। ग्रामीण अपना ट्रांसफार्मर स्वयं के वाहन से लेकर जाते हैं तो वहां उसको पीने का पानी एवं बैठने की सुविधा तक मुहैया नहीं कराई जा रही।

महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके आत्मसम्मान को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही महतारी वंदन योजना

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के खरसिया में महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त का भुगतान करते हुए प्रदेश की 69,15,994 महिलाओं के खातों में 1000-1000 रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह योजना महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके आत्मसम्मान को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आर्थिक सहयोग प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और परिवार की आर्थिक मजबूती में सहायक सिद्ध होगा। सितम्बर माह की 19वीं किस्त में कुल 647.13 करोड़ रुपये का अंतरण किया गया। इस भुगतान को मिलाकर अब तक योजना के तहत औसतन 69,28,334 पात्र महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में 12,376.19 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। गौरतलब है कि 1 मार्च 2024 से शुरू की गई महतारी वंदन योजना का उद्देश्य विवाहित एवं 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को हर माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना प्रदेश की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि यह योजना प्रदेश की महिलाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सम्मान प्रदान कर रही है। यह उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है और उन्हें आर्थिक प्रगति की मुख्यधारा से जोड़ रही है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि महिलाओं के विकास, सुरक्षा और स्वाभिमान को प्राथमिकता देते हुए महतारी वंदन योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से संवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठाती रहेगी।

मिलाद-उन-नबी के अवसर पर निकला जुलूस

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी। देवरी नगर में ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा बड़ी धूम धाम के साथ जुलूस निकाला गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के अवसर पर गांधी वार्ड से गुटी खान के नेतृत्व में जुलूस शुरू हुआ और जुलूस गांधी वार्ड से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए सिविल लाइन संजय नगर बाजार वार्ड की छोटी मस्जिद से नगर पालिका चौराहे से होते रंगरेज मस्जिद पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में डीजे बैंड पार्टी के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। जुलूस में इस्लाम धर्म के मानने वाले बच्चे, बूढ़े और जवान सभी प्यारे नबी के जश्न में शामिल थे। सिर में हरी पगड़ी, रंग-बिरंगे पोशाक, कलमा लिखे झंडे सहित राष्ट्रीय झंडे को लहराते नाथ और दुआ पढ़ते आगे की ओर बढ़ रहे थे। जुलूस के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मिलाद-उन-नबी इस्लामी पंचांग के तीसरे महीने रबी-उल-अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी काफी खास दिन माना जाता है। इसी माह में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था।

मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ की पहल से आकार ले रहा ओबीसी आरक्षण का सपना

(पेज 1 का शेष)

इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर आज प्रदेश में ओबीसी को जो आरक्षण मिलेगा उसकी नींव कमलनाथ ने रखी थी। उनका ही प्रयास था कि इस वर्ग की वर्षों की मांग पूरी होगी।

कमलनाथ की पहल 18 महीनों में बड़ा कदम

वर्ष 2018 में जब कमलनाथ ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उन्होंने तत्काल ही ओबीसी आरक्षण की कवायद शुरू की। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के बिना विकास की परिभाषा अधूरी है। कमलनाथ सरकार ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव लाकर इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। हालांकि यह सफर इतना आसान नहीं रहा। राजनीतिक विरोध और कानूनी पेचों ने इस फैसले को लंबे समय तक लटकाए रखा।

शिवराज सरकार में मामला उलझा

कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद प्रदेश की सत्ता एक बार फिर भाजपा के हाथों में आई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस दौरान ओबीसी आरक्षण का मुद्दा साजिशन कानूनी दांव-पेंच में उलझा दिया गया। चार साल तक यह मामला न्यायालय और फाइलों के बीच अटका रहा। यदि शिवराज सिंह चौहान उस समय सर्वदलीय बैठक कर सभी दलों को विश्वास में लेते, तो यह आरक्षण पहले ही लागू हो सकता था। लेकिन राजनीतिक रणनीति और समय टालने की प्रवृत्ति ने लाखों ओबीसी समुदाय के लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखा।

सर्वदलीय बैठक का श्रेय कमलनाथ को

सर्वदलीय बैठक में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने पर सहमति बनी, तो कई नेताओं ने साफ कहा कि इसका श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ही जाता है। उनकी दूरदर्शिता और पहल ने ही इस दिशा में रास्ता खोला था। सत्ता से बाहर रहने के बावजूद कमलनाथ ने जनप्रतिनिधि होने के नाते समाज के हर वर्ग से संवाद बनाए रखा और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनकी मदद भी की। यही कारण है कि आज भी ओबीसी समाज का बड़ा हिस्सा उन्हें अपना नेता मानता है।

ओबीसी आरक्षण का सामाजिक महत्व

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का लागू होना केवल एक कानूनी या राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। प्रदेश की लगभग आधी आबादी ओबीसी वर्ग से आती है। इन्हें शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देना लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। लंबे समय से इस समुदाय के लोग अपने हिस्से का हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब जब सर्वदलीय सहमति बन गई है, तो यह विश्वास किया जा सकता है कि उनकी पीढ़ियों को नए अवसर मिलेंगे और सामाजिक संतुलन स्थापित होगा। कमलनाथ की पहल और सर्वदलीय सहमति यह साबित करती है कि यदि राजनीति से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए निर्णय लिया जाए तो लोकतंत्र और भी मजबूत होता है।

समाज के साथ निरंतर जुड़ाव

सत्ता से बाहर रहते हुए भी कमलनाथ की सक्रियता कम नहीं हुई है। वे लगातार अपने क्षेत्र और प्रदेश के लोगों से जुड़े रहते हैं। चाहे व्यक्तिगत समस्याएं हों या सामूहिक मुद्दे, कमलनाथ हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यही कारण है कि आज भी जनता उन्हें भरोसेमंद नेता के रूप में देखती है। उनका यह रवैया बताता है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम भी हो सकती है।

छिंदवाड़ा मॉडल विकास का आदर्श

कमलनाथ का राजनीतिक सफर केवल आरक्षण की पहल तक सीमित नहीं है। उनके नेतृत्व में छिंदवाड़ा मॉडल देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी विकास का आदर्श स्वरूप माना जाता है। छिंदवाड़ा, जो कभी पिछड़े जिलों की सूची में गिना जाता था, आज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में मिसाल बन चुका है। यहां रोजगार के अवसर बढ़े हैं, किसानों को आधुनिक सुविधाएं मिली हैं और बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है। कमलनाथ का मानना है कि यदि एक सांसद या नेता अपनी नीयत और दूरदर्शिता से काम करे तो किसी भी क्षेत्र का कायाकल्प किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार

(पेज 1 का शेष)

इनमें वे नेता शामिल हैं जिन्होंने लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया और सरकार बनने में अहम योगदान दिया। साथ ही पहली बार विधायक बने कुछ युवा चेहरों को भी मंत्री पद देकर भविष्य की राजनीति के लिए तैयार किया जा सकता है।

सभी नेता हुए सक्रिय

मंत्रिमंडल विस्तार की आहट के साथ ही भाजपा नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। राजधानी रायपुर से लेकर दिल्ली तक नेताओं की आवाजाही तेज हो गई है। कोई संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहा है, तो कोई अपने क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन कर समर्थन जुटा रहा है। सोशल मीडिया पर भी नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है, ताकि केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी लोकप्रियता का संदेश पहुंचाया जा सके।

संगठन और सरकार में तालमेल

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार से संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब तक अकेले मोर्चा संभालते रहे हैं, लेकिन नए मंत्रियों की टीम के जुड़ने से प्रशासनिक निर्णय तेजी से होंगे। साथ ही, पार्टी को भी यह संदेश मिलेगा कि मेहनत करने वालों को इनाम मिलता है।

भाजपा की रणनीति

भाजपा नेतृत्व अच्छी तरह जानता है कि आगामी लोकसभा चुनाव और फिर निकट भविष्य में होने वाले स्थानीय चुनावों में पार्टी को संगठन को मजबूत करना होगा। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन साधना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल इलाकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरह रायपुर-बिलासपुर जैसे शहरी क्षेत्रों से भी चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बनने के बाद डेढ़ साल तक मंत्रिमंडल का विस्तार न होना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा आंतरिक खींचतान में उलझी हुई है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा जनता के मुद्दों पर काम करने के बजाय पद बांटने की राजनीति में व्यस्त है। भाजपा का तर्क है कि संगठनात्मक मजबूती और दीर्घकालिक रणनीति के लिए विचार-विमर्श जरूरी था।

जनता की सरकार से अपेक्षाएँ

आम जनता की नजर इस बात पर है कि नए मंत्रियों के आने के बाद विकास कार्यों की रफ्तार कितनी तेज होगी। किसानों से लेकर युवाओं और महिलाओं तक की अपेक्षाएँ सरकार से जुड़ी हुई हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं पर ठोस काम होने की उम्मीद है। पार्टी के अंदर भी यह सवाल बना हुआ है कि आखिर किसे मौका मिलेगा और कौन बाहर रह जाएगा। भाजपा में इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार "योगदान और जनाधार" के आधार पर होने की संभावना जताई जा रही है। वरिष्ठ नेताओं को तो जगह मिलेगी ही, लेकिन युवा चेहरों के शामिल होने से सरकार को नई दिशा भी मिल सकती है। कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ भाजपा में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बनने वाली यह नई टीम सरकार के कामकाज को गति देने के साथ-साथ संगठन को भी ऊर्जा देगी। किस नेता को कौन-सी जिम्मेदारी मिलेगी, यह तो आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि भाजपा इस विस्तार को 2028 की चुनावी तैयारी के रूप में भी देख रही है।

सम्पादकीय

ट्रंप के बड़बोलेपन से बिगड़ते भारत, रूस और चीन से अमेरिका के रिश्ते

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इस दौर में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। शीत युद्ध के बाद से वैश्विक समीकरणों में भारत को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखा जाता रहा है। आज जब रूस और चीन एक साझा मंच पर खड़े दिखाई देते हैं और अमेरिका अपनी वैश्विक बादशाहत बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, तो यह आशंका स्वाभाविक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह डर सताने लगे कि कहीं उसने भारत को खो तो नहीं दिया। भारत बीते दशक में जिस तेजी से एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है, उसका असर केवल एशिया तक सीमित नहीं रहा बल्कि यूरोप और अमेरिका की नीतियों पर भी दिखाई देता है। अमेरिका के लिए भारत केवल एक संभावित बाजार नहीं है, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने का अहम साधन भी है। ऐसे में अगर भारत रूस और चीन के करीब जाता है, तो अमेरिकी रणनीति के लिए यह एक बड़ा झटका होगा।

भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है। रक्षा क्षेत्र से लेकर ऊर्जा आपूर्ति तक रूस भारत का भरोसेमंद साझेदार रहा है। एस-400 मिसाइल प्रणाली हो या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण भारत ने कई बार अमेरिकी दबावों को नकारते हुए रूस के साथ समझौते किए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, उस समय भी भारत ने खुलेआम किसी पक्ष का समर्थन करने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया। रूस से कच्चे तेल की खरीद भारत ने जारी रखी, जिससे अमेरिका को यह संदेश गया कि भारत उसके कहने भर पर अपनी रणनीति नहीं बदलेगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और संघर्ष नई बात नहीं है। भारत भले ही चीन पर पूरी तरह से भरोसा न करता हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में चीन की मौजूदगी भारत को रणनीतिक रूप से संतुलन साधने पर मजबूर करती है। अमेरिका को यह डर यहीं से है कि कहीं भारत इस बहुपक्षीय सहयोग के बहाने रूस और चीन के करीब न आ जाए। अमेरिका की चिंता केवल भू-राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। भारत, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। अमेरिका जानता है कि आने वाले दशक में वैश्विक आपूर्ति शृंखला और तकनीकी नेतृत्व में भारत की अहम भूमिका होगी। आईटी, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष अनुसंधान और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की क्षमता लगातार बढ़ रही है। यदि भारत अपनी प्राथमिकताएँ रूस और चीन के साथ साझा करने लगता है तो यह न केवल अमेरिकी कूटनीति के लिए चुनौती होगी बल्कि अमेरिकी कंपनियों के लिए भी अवसरों का नुकसान साबित होगा।

भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह किसी भी खेमे में पूरी तरह शामिल नहीं हुआ है। शीत युद्ध के दौर में 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' से लेकर आज के 'मल्टी-अलाइनमेंट' तक भारत ने हमेशा अपनी स्वायत्त विदेश नीति पर जोर दिया है। यही कारण है कि भारत QUAD जैसे मंचों पर अमेरिका और जापान के साथ खड़ा है, तो ब्रिक्स और SCO में रूस-चीन के साथ भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत की इस बहुआयामी कूटनीति ने अमेरिका को असहज किया है क्योंकि वॉशिंगटन चाहता है कि भारत साफ तौर पर उसके खेमे में खड़ा हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने सबसे बड़ी दुविधा यही है कि भारत को अपने साथ बनाए रखने के लिए वह कितनी रियायतें दे सकता है। रूस से हथियार खरीदने के मुद्दे पर भारत को 'काट्सा' कानून से छूट देना हो या यूक्रेन युद्ध पर भारत की तटस्थ भूमिका को स्वीकार करना अमेरिका बार-बार पीछे हटता दिखा है। कारण साफ है, अमेरिका यह जोखिम नहीं लेना चाहता कि भारत पूरी तरह रूस और चीन की ओर खिसक जाए। भारत के लिए उसकी अपनी सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक हित सर्वोपरि हैं। चीन के खिलाफ रणनीतिक संतुलन बनाना, रूस से सस्ते तेल की आपूर्ति पाना और अमेरिका से तकनीकी एवं निवेश सहयोग हासिल करना यह तीनों भारत की विदेश नीति के अहम स्तंभ बन चुके हैं। भारत यह भलीभांति समझता है कि अगर वह केवल अमेरिका या केवल रूस-चीन पर निर्भर होता है, तो उसकी स्वायत्तता सीमित हो जाएगी। इसलिए भारत संतुलन की राजनीति खेल रहा है, और यही संतुलन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

सियासी गहमागहमी

जीतू पटवारी के बिगड़ेल बोल पड़ सकते हैं कांग्रेस को महंगे

राजनीति में अक्सर नेताओं की जुबान फिसलती है, परंतु कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की जुबान तो मानो स्थायी छुट्टी पर चली गई है। कभी वे फुटबॉल टीम से तुलना कर जाते हैं, तो कभी महिलाओं पर ऐसे बयान दे बैठते हैं जो न केवल पार्टी की इज्जत का गोल कर देते हैं बल्कि जनता को हंसी और गुस्से का मिला-जुला पैकेज भी थमा देते हैं। कहते हैं कि राजनीति में विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन यहां तो बयान ही हथियार बन गए हैं। कांग्रेस को लगता होगा कि उनके नेता जनता को लुभा रहे हैं, पर सच यह है कि जनता अब बयान सुनकर मनोरंजन जरूर करती है, वोट देना भूल जाती है। महिलाओं पर पटवारी के बिगड़ेल बोल बतौर नेता उनकी छवि पर सवाल उठाते हैं। राजनीति में जहां महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल बन रही हैं, वहां पटवारी का बयान मानो कांग्रेस को 19वीं सदी के गली-कूचों में खड़ा कर देता है। विपक्ष को बैठे-बिठाए मुद्दा मिल गया और जनता को मुफ्त का तमाशा। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस "बयानबाजी स्पेशल" से पार्टी की नाव कैसे पार लगाती है।

मप्र भाजपा में निगम मंडल में पद पाने की लगी होड़

मध्यप्रदेश भाजपा में इन दिनों हालत कुछ यूं हैं जैसे मेले में मुफ्त हलवा बांटा जा रहा हो और भीड़ कढ़ाही पर टूट पड़ी हो। निगम–मंडल की कुर्सियाँ भले ही लकड़ी की हों, लेकिन उनके लिए नेताओं का आकर्षण ऐसा है मानो ये स्वर्ण सिंहासन हों। पार्टी कार्यकर्ता वर्षों की तपस्या, पसीने और पन्ने–पोस्टरों का हिसाब अब कुर्सी के रूप में वसूलना चाहते हैं। आलम यह है कि जिन नेताओं को जनता याद भी नहीं करती, वे भी अपने पुराने पोस्टरों की धूल झाड़कर सक्रिय हो गए हैं। कोई अपनी वफादारी गिनवा रहा है, तो कोई अपनी "चाय पर चर्चा" वाली सेल्फी दिखाकर वरिष्ठता साबित कर रहा है। सबसे दिलचस्प दृश्य तो तब होता है जब पुराने नेता और नए नेता एक ही कुर्सी के लिए लाइन में लग जाते हैं। मानो यह कुर्सी नहीं, बल्कि स्वर्ग का वीआईपी पास हो। पार्टी नेतृत्व के सामने समस्या यह है कि अगर सभी की भूख मिटानी हो, तो निगम–मंडल से ज्यादा तो नए निगम बनाने पड़ेंगे। राजनीति में सेवा भाव की बातें चाहे जितनी हों, पर असली सेवा कुर्सी से ही होती है- यह अब सबको समझ आ गया है। इसीलिए निगम–मंडल की दौड़ आजकल भाजपा में ओलंपिक से भी ज्यादा रोमांचक दिखाई दे रही है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

मोदी जी, पंजाब मे बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड मे भी स्थिति बेहद चिंताजनक है।

ऐसे मुश्किल समय मे आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत आवश्यक है। हजारो परिवार अपने घर, जीवन और अपनो को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे है। -राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्यप्रदेश के किसान यूरिया खाद के लिए दर-दर भटक रहे है, सरकार मौन क्यों? मध्यप्रदेश के किसान इन दिनो खाद की भारी किल्लत झेल रहे है। सबसे बड़ी समस्या यूरिया खाद की उपलब्धता की है। स्थिति यह है कि किसान लंबे समय से कतारो मे खड़े होकर भी खाद नही पा रहे है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

राजनीतिक विश्लेषक और प्रखर वक्ता के रूप में पहचान रखते हैं डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी

समता पाठक/जगत प्रवाह

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म 15 सितंबर 1939 को मायलापोर, चेन्नई (तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी) में हुआ। उनके पिता, सितारामन सुब्रमण्यम, भारतीय सांख्यिकी सेवा में अधिकारी थे और केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली में निदेशक तथा सरकार के सांख्यिकी सलाहकार भी रहे। उन्होंने अपनी स्नातक पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से गणित में पूरी की, इसके बाद कोलकाता के भारतीय सांख्यिकीय संस्थान से सांख्यिकी में मास्टर्स किया।फिर रॉकफेलर छात्रवृत्ति पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए, जहाँ से उन्होंने 1965 में अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। उनके थीसिस सलाहकार नोबल विजेता साइमन कुजनेट्स थे और साथ ही उन्होंने नोबल पुरस्कार विजेता पॉल ऐ. सैम्युलसन के साथ इंडेक्स नंबर सिद्धांत पर लेख भी सह-लेखन किए। हार्वर्ड से पीएचडी प्राप्त करने के बाद, डॉ. स्वामी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर (1965) और बाद में एसोसिएट प्रोफेसर (1969) बने। भारत लौटकर उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चीन अध्ययन की कुर्सी लेने का निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन उनके आर्थिक-राजनीतिक दृष्टिकोणों के कारण यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। इसके बाद वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में गणितीय अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने, लेकिन तत्कालीन सामाजिकवादी आर्थिक नीति के विरोध के चलते उनका पद (1970-72 के बीच) समाप्त कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित किया। 1978 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र ने 'डेवलपिंग कंट्रीज के मध्य आर्थिक सहयोग' रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक माननीय समूह में शामिल किया। 1994 में वे प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के अधिन आयोग 'लेबर स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड' के अध्यक्ष बने। आर्थिक और सामाजिक आंदोलनों में उनकी भागीदारी से प्रेरित होकर, वे सरवदया आंदोलन से जुड़े और 1970 के दशक में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शुमार हुए। वे 1990-91 में वाणिज्य तथा कानून और न्याय मंत्री रहे, जहाँ उन्होंने आर्थिक सुधारों की रूपरेखा पेश की, जिसे बाद में लागू किया गया। वे तीन बार लोकसभा और तीन बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 2013 में जनता पार्टी अध्यक्ष के रूप में भाजपा में विलय का नेतृत्व किया। 2016 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्य बनाया गया। डॉ. स्वामी सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएँ दर्ज कर चुके हैं। विशेषकर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में उन्होंने हाई-प्रोफाइल कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने पी. चिदंबरम और सोनिया गांधी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की। उन्हें मुक्त बाजार अर्थशास्त्र, हिंदुत्व और सांस्कृतिक आत्मानुभूति के संगम के रूप में जाना जाता है। डॉ. स्वामी तमिल, हिंदी, अंग्रेजी में दक्ष हैं और चीनी भाषा में भी बातचीत कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता उल्लेखनीय है—उनके लाखों अनुयायी हैं, और आरएसएस से उनकी गहरा संबंध रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने "रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने" की उनकी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जो उनके सामाजिक-धार्मिक हस्तक्षेप का नया उदाहरण था। डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी एक विश्व-प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, शिक्षाविद्, राजनेता और विधिवेत्ता हैं। हार्वर्ड और IIT जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में शिक्षण, संयुक्त राष्ट्र में योगदान, जनहित अभियानों व जनांदोलन में सक्रियता, आर्थिक सुधारों में निर्णायक भूमिका, और सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्रों में लगातार सक्रियता उनकी जीवन यात्रा को एक अनूठी पहचान देती है।

एससीओ समिट : भारत, रूस और चीन नया वैश्विक मंच

-विजया पाठक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन में शंघाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर भारत लौट चुके हैं। एससीओ समिट से निकले संदेश और तस्वीरों को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। सम्मेलन में जिस तरह से पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नजर आए उसके अपने मायने हैं। जानकारों का मानना है कि भारत ने इस सम्मेलन के जरिये अमेरिका को संदेश दे दिया है। संदेश है कि हम ट्रंप के टैरिफ के सामने झुकने वाले नहीं हैं। खास बात है कि एससीओ सम्मेलन की तस्वीरों पर जिस तरह से अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है वह ट्रंप की बेचैनी को साफ दिखा रही है। अमेरिका की प्रतिक्रिया से साफ है कि वह भारत के हर कदम पर नजर रख रहा है।

भारत की एससीओ में चीन और रूस से करीबी से ट्रंप को मिर्ची लग रही है। इस बात का अंदाजा ट्रंप की इस प्रतिक्रिया से समझा जा सकता है। एससीओ सम्मेलन के खत्म होने के कुछ समय बाद ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड संबंधों की आलोचना करते हुए उसे एकतरफा बताया। ट्रंप का तर्क था कि भारत, अमेरिका को 'भारी मात्रा में सामान' निर्यात करता है, लेकिन अमेरिकी कंपनियों को अधिक टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ट्रंप के अनुसार, भारत ने ऐतिहासिक रूप से 'किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक' टैरिफ लगाए हैं, जिससे उनके अनुसार 'कई दशकों' तक चलने वाला असंतुलित और अनुचित व्यापार संबंध बना है। उन्होंने दावा किया कि इस स्थिति ने अमेरिकी बिजनेस को नुकसान में डाल दिया है, जबकि अमेरिका भारत का 'सबसे बड़ा ग्राहक' बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस से भारत की डिफेंस और तेल की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत अपना अधिकांश तेल और डिफेंस साजोसामान रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका से बहुत कम खरीदता है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अब अपने टैरिफ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है।

अमेरिका में हो रही ट्रंप नीति की आलोचना

खास बात है कि ट्रंप की नीति को लेकर अपने घर में ही आलोचना झेलनी पड़ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप को खरी-खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि भारत को रूस के साथ शीत युद्ध के संबंधों से दूर रखने और चीन के बारे में उसे सावधान करने के पश्चिमी देशों के दशकों के प्रयास डोनाल्ड ट्रंप की 'विनाशकारी' टैरिफ नीति के कारण विफल हो गए हैं। बोल्टन ने यह भी आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतिक कूटनीति की कमी ने शी जिनपिंग को पूर्वी एशिया में स्थिति को नया रूप देने का मौका दिया है।

परिवार के लिए अमेरिकी हित दांव पर?

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जेक सुलिवन ने भी ट्रंप को उनकी रणनीति के लिए आड़े हाथों लिया है। पूर्व एनएसए ने सुलिवन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपने परिवार के व्यापारिक सौदों के लिए भारत के साथ संबंधों की बलि दे दी है। उन्होंने कहा कि हितों के स्पष्ट टकराव में, ट्रंप परिवार पाकिस्तान में एक क्रिप्टो वेंचर में शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की चापलूसी कर रहे हैं। सुलिवन ने कहा कि अमेरिका को भारत के साथ तकनीक, प्रतिभा और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए था। इससे पहले भी सुलिवन ने ट्रंप पर हमलावर होते हुए उनकी नीतियों को विनाशकारी बताया था। सुलिवन ने कहा था कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ 'व्यापक व्यापार आक्रमण' लागू कर नई दिल्ली को चीन की ओर धकेल रहे हैं। उनका कहना था कि जब मैं अब इन जगहों पर जाता हूं और नेताओं से बात करता हूं, तो वे अमेरिका से जोखिम कम करने की बात करते हैं। वे अब अमेरिका को एक बड़े विघटनकारी देश के रूप में देखते हैं, एक ऐसे देश के रूप में जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुलिवन ने साफ कहा था कि जहां चीन वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार खिलाड़ी की तरह दिख रहा है, वहीं 'अमेरिकी ब्रांड टॉयलेट में है।

अमेरिका ने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क लगाया है। इसके अलावा रूस से तेल व्यापार कम करने से इनकार करने पर अतिरिक्त 25% शुल्क और जोड़ दिया गया, जिससे कुल ड्यूटी 50% तक पहुंच गई है। भारत ने इन शुल्कों को "अनुचित और अकारण" बताया है। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत-अमेरिका संबंध पिछले दो दशकों के सबसे निचले स्तर पर माने जा रहे हैं, जिसे ट्रंप प्रशासन की शुल्क नीति और नई दिल्ली के प्रति उसके लगातार आलोचनात्मक रुख ने और गहरा किया है।

जानते हैं SCO बैठक की बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलग-अलग मुलाकात की। दोनों बैठकों की अवधि लगभग 50-50 मिनट रही, जिसमें व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खास बात यह रही कि पुतिन और मोदी की बातचीत सिर्फ बैठक कक्ष तक सीमित नहीं रही। पुतिन ने मोदी को अपनी कार में आमंत्रित किया और रास्ते में भी लंबा संवाद जारी रखा. इस कदम को भारत-रूस संबंधों की गहराई का प्रतीक माना गया। बैठक के बाद भारत-चीन सीधी उड़ानों की बहाली और दिसंबर में पुतिन की भारत यात्रा की घोषणा ने इन मुलाकातों को और ऐतिहासिक बना दिया।

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

महानदी के जल को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा में विवाद

छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के बीच बहने वाली महानदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद गहरा गया है। हालांकि यह विवाद आठ दशक से भी ज्यादा पुराना है। समय-समय पर विवाद के हल खोजे जाते रहे हैं,लेकिन अब तक सर्वमान्य हल निकल नहीं पाया है। परंतु अब बदले राजनितिक परिदृश्य में इस विवाद का स्थायी हल निकलने की उम्मीद बढ़ गई है। एक तो अब दोनों राज्यों में एक ही दल भाजपा की सरकारें हैं,दूसरे केंद्र में भाजपा के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, जो बुनियादी समस्याओं के निराकरण में माहिर हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहनचरण मांझी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और केंद्र सरकार से समस्या निवारण में सहयोग मांगा है। अब सवाल खड़ा होना जरूरी है कि इस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद इतना जटिल क्यों बन गया कि और सुलट क्यों नहीं रहा है।

छत्तीसगढ़ और ओडिशा भू-क्षेत्र की महानदी सबसे बड़ी नदी है। रामायण और महाभारत काल में भी इस नदी का अस्तित्व मौजूद था। तब इसे चित्रोत्पला, महानंदा और नीलोत्पला नामों से जाना जाता था। इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर सिहावा से निकलकर राजिम में पहुंचता है, तब इसमें पैरी और सोंदुर नदियां भी मिल जाती हैं। इन नदियों का जल विलय होने के साथ ही यह नदी विशाल रूप धारण कर लेती है। इसके बाद ऐतिहासिक नगर आरंग और सिरपुर से बहती हुई जब शिवरीनारायण में पहुंचती है तो अपने नाम के अनुरूप महानदी का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। महानदी के तट पर ही धमतरी, कांकेर, चारामा, राजिम और चंपारण बसे हैं। शिवरीनारायण एक धार्मिक नगरी है। यहीं से यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर न बहकर पूर्व दिशा में बहने लग जाती है। संभलपुर में प्रवेश करने के साथ ओडिशा में बहने लगती है। इसके प्रवाह का आधे से अधिक भाग छत्तीसगढ़ में है। संभलपुर के आगे बलांगीर और कटक से निकलकर महानदी कुल 851 किमी की लंबी यात्रा कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस बीच इसमें पैरी, सोंदुर, शिवना, हंसदेव, अरपा, जोंक,ईब, मांड,केलो,बोरई,कंजी,लीलार और तेल नदियां भी मिलती हैं। कटक से लगभग 12 किमी पहले महानदी कई धाराओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है।

इस नदी पर कुल 253 बाँध,14 छोटे बांध और 13 एनीकट हैं। हीराकुंड, रुद्री,गंगरेल और मिनीमाता हसदेव बांगो जैसे प्रमुख बांध बंधे हैं। 6 बिजली संयंत्र भी बने हुए हैं। महानदी ही पूर्वी मध्यप्रदेश और ओडिशा की सीमाओं को निर्धारित करती है। गिब्सन नामक अंग्रेज ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि संभलपुर के निकट हीराकुंड का जो द्वीप क्षेत्र है, यहां एक समय हीरा मिला करते थे। जिनकी खपत रोम में होती थी। 2011 की जनगणना के अनुसार महानदी क्षेत्र में रहने वाले करीब 30 लाख लोगों की आबादी की आजीविका इसी नदी के पानी पर निर्भर है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनने से पहले तक रोम के सिक्के मिल जाया करते थे, इसी तथ्य को गिब्सन ने इस क्षेत्र में हीरे की खदानें होने से जोड़ा है। चीनी यात्री व्हेनसांग ने अपनी यात्रा कथा में लिखा है कि मध्यप्रदेश से हीरों का व्यापार ओडिशा के कलिंग में होता था। इन विवरणों से पता चलता है कि महानदी और हीराकुंड क्षेत्र में कभी हीरे की खदानें रही हैं।

छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 55 प्रतिशत हिस्से का पानी महानदी में जमा होता है। यह नदी और इसकी सहायक नदियों के ड्रेनेज एरिया का 53.90 फीसदी हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। इसका 45.73 प्रतिशत ड्रेनेज एरिया ओडिशा और 0.35 प्रतिशत अन्य राज्यों में हैं। हीराकुंड बांध तक महानदी का जल ग्रहण क्षेत्र 82,432 वर्ग किमी हैं, जिसमें से 71,424 वर्ग किमी क्षेत्र छत्तीसगढ़ में हैं, जो कि इसके संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र का 86 प्रतिशत है। हीराकुंड बांध में महानदी का बहाव 40,773 एमसीएम है, इसमें से 35,308 एमसीएम का योगदान छत्तीसगढ़ देता है। जबकि इस समय छत्तीसगढ़ केवल 9000 एमसीएम पानी का उपयोग कर रहा है, जो कि महानदी के हीराकुंड में उपलब्ध पानी का महज 25 प्रतिशत है। हालांकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा था कि छत्तीसगढ़ केवल 15 प्रतिशत पानी का उपयोग करता है।

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में महानदी पर 9 छोटे-बड़े बांध हैं। इन्हीं बांधों को लेकर विवाद की शुरुआत 2016 में हुई थी। तब ओडिशा सरकार ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महानदी की सहायक नदियों पर लघु बांध और एनीकट बनाकर ओडिशा को मिलने वाले पानी को कम कर दिया है। इस कारण गर्मियों में नदी का जलस्तर इतना गिर जाता है कि सिंचाई और पीने के पानी की किल्लत खड़ी हो जाती है। जबकि छत्तीसगढ़ का कहना है कि वह अपने क्षेत्र में ही जल का भंडारण करता है। अब ओडिशा चाहता है कि छत्तीसगढ़ महानदी की सहायक नदियों पर कोई बांध नहीं बनाए और जल के प्रवाह को बाधित न करे। इस विवाद को निपटने के लिए 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया था,लेकिन प्रकरण का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ के बड़े भू-भाग में कुंए और नलकूपों का जलस्तर भी यही बांध बनाए रखते हैं। लेकिन यहां सोचनीय पहलू है कि ज्यादातर ट्रिब्यूनल नदियों से जुड़े अंतर-राज्यीय जल विवाद निपटाने में सफल नहीं हो पाए हैं,इसलिए राज्य सरकारों को आपसी सहमति से इन समस्याओं का हल ढूढ़ने की जरूरत है।

बेलगाम ज़ुबान और बिगड़ी राजनीतिक समझ का उदाहरण है जीतू पटवारी का विवादित बयान

कांग्रेस में मार्गदर्शन का अभाव

जगत विजन जैसे कई राजनीतिक विश्लेषक पहले ही कह चुके हैं कि पटवारी को समझदार और अनुभवी मार्गदर्शक की आवश्यकता है। मगर कांग्रेस नेतृत्व शायद इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा। यही कारण है कि पटवारी बार-बार ऐसे बयान देते हैं, जिनसे पार्टी को नुकसान होता है।

कांग्रेस की महिला छवि पर धक्का

महिलाएँ केवल मतदाता ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए आधार स्तंभ हैं। भाजपा ने लंबे समय से महिलाओं के बीच योजनाएँ और कार्यक्रमों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की है। वहीं कांग्रेस महिलाओं के बीच अपनी स्वीकार्यता खोती जा रही है। अब पटवारी के इस बयान ने कांग्रेस की महिला छवि को और धक्का दे दिया है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता खुद इस बयान से असहज हैं। वे कैसे जनता के बीच जाकर प्रचार करेंगी, जब उनके ही प्रदेशाध्यक्ष महिलाओं पर गलत आरोप लगाते हों?

कांग्रेस का आत्मघाती रास्ता

एक बार यह मान भी लें कि पटवारी ने बयान भावनाओं में आकर दिया हो, मगर सवाल यह है कि क्या प्रदेशाध्यक्ष को इतना भी संयम नहीं होना चाहिए कि वे अपनी ही पार्टी की साख और महिला मतदाताओं की अस्मिता से खिलवाड़ न करें? कांग्रेस पहले ही हार-जीत की दहलीज पर खड़ी है। ऐसे में नेतृत्व यदि आत्मघाती रास्ता अपनाएगा तो पार्टी की हालत और भी बदतर हो जाएगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि पटवारी के इस बयान से कांग्रेस को आगामी चुनावों में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

पटवारी को लगाम की जरूरत

जीतू पटवारी का यह बयान केवल एक जुबानी फिसलन नहीं है। यह कांग्रेस की उस गहरी समस्या का प्रतीक है, जिसमें संगठन अनुशासन और मार्गदर्शन के अभाव में बिखरा हुआ है। पटवारी को अब यह समझना होगा कि वे प्रदेशाध्यक्ष हैं, कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं। उनके एक-एक शब्द का असर लाखों लोगों पर पड़ता है। उन्हें विवेकानंद के संदेश को आत्मसात करना चाहिए, न कि उसे अपने बेतुके बयानों से उलट देना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व को भी अब तय करना होगा कि वह ऐसे बेलगाम नेताओं पर कब लगाम लगाएगा। यदि अभी भी नियंत्रण नहीं किया गया तो कांग्रेस को न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि बिहार और अन्य आगामी राज्यों के चुनावों में भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजनीति केवल नारों और भाषणों का खेल नहीं है। यह जिम्मेदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता का क्षेत्र है। यदि कांग्रेस इस मूलमंत्र को नहीं समझती तो पटवारी जैसे नेता बार-बार उसकी नाव को डुबाने का काम करते रहेंगे।

सच्चे शिक्षक वे हैं जो हमें खुद के लिए सोचना सिखाते हैं

आज की बात
प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

हमारे जीवन की पहली नींव माता-पिता रखते हैं और उसे मजबूत आकार देने का कार्य शिक्षक करते हैं। शिक्षक केवल पढ़ाई नहीं कराते, वे मिट्टी को गढ़कर सुंदर मूर्ति बनाते हैं। साधारण से साधारण छात्र को भी वे इस प्रकार तराशते हैं कि वह असाधारण बन सके। बच्चों के जीवन में शिक्षक का स्थान केवल गाइड या इंस्ट्रक्टर का नहीं होता, बल्कि वे पथप्रदर्शक, मार्गदर्शक और जीवन-निर्माता होते हैं। वे आत्मविश्वास जगाते हैं, ज्ञान का दीप जलाते हैं और कठिन राहों पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। शिक्षक होना आसान नहीं है। पसीने को स्याही बनाकर पेन में भरना पड़ता है, तभी बच्चों की किस्मत लिखी जाती है। कभी सिलेबस बदल जाता है तो कभी तकनीक, लेकिन शिक्षक पहले खुद सीखता है, फिर बच्चों को सिखाता है। शिक्षक बच्चों की उम्र से उम्र मिलाकर दौड़ना पड़ता है, अगर शिक्षक धीमा पड़ जाए तो छात्र तेज कैसे भागेंगे? शिक्षक की जिंदगी का गणित चाहे कितना भी उलझा हो, पर वह बच्चों के सवालों को हमेशा सुलझाता है। जिस प्रकार शिल्पकार पत्थर को तराशकर उत्कृष्ट कलाकृति बनाता है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थियों के दोष दूर कर उन्हें काबिल बनाता है। जैसे एक मजबूत भवन के लिए पक्की नींव आवश्यक होती है, वैसे ही बेहतर जीवन के लिए शिक्षक का सानिध्य और मार्गदर्शन जरूरी है। शिक्षक ही वह शख्सियत है जो छात्रों के जीवन को केवल ज्ञानवान नहीं, बल्कि मूल्यवान बनाते हैं।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति

भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वे महान दार्शनिक, मेधावी शिक्षक और शिक्षा-प्रेमी थे। 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में कार्य किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। बाद में वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। इतने ऊँचे पदों पर पहुँचने के बाद भी उनकी सादगी और शिक्षा के प्रति समर्पण अद्भुत था। उनका मानना था कि "एक देश की ताकत वास्तव में उसके युवा लोगों में निहित होती है, जिन्हें उनके शिक्षक सही दिशा प्रदान करते हैं।" यही कारण है कि आज भी उनका जीवन और विचार हर शिक्षक के लिए आदर्श बने हुए हैं।

बीते समय की झलक

लगभग 20–25 साल पहले शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि वे छात्रों को नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों और जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। वे बताते थे कि बड़ों का सम्मान कैसे करना है, समाज में व्यवहार कैसा रखना चाहिए और कठिनाइयों में संयम कैसे बनाए रखना है। तब शिक्षा कक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को गढ़ने का माध्यम थी।

आज की स्थिति पर चिंता

आज के आधुनिक युग में जब कंप्यूटर, मोबाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव बढ़ रहा है, शिक्षा का स्वरूप भी बदल गया है। अब पढ़ाई अधिक तकनीकी और परीक्षा-केंद्रित हो गई है। शिक्षकों और छात्रों के बीच व्यक्तिगत रिश्ता पहले जैसा गहरा नहीं रह गया है। संस्कार, नैतिक मूल्य और सामाजिक सीख देने की परंपरा कहीं कम होती जा रही है। यह चिंता का विषय है, क्योंकि शिक्षा केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन को गढ़ने वाली होनी चाहिए। शिक्षक आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उन्हें आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, सामाजिक संस्कार और मानवता की रोशनी बच्चों के जीवन में भरनी होगी। शिक्षक ही राष्ट्र के सच्चे निर्माता हैं। यदि वे बच्चों में केवल ज्ञान नहीं, बल्कि संस्कार और आत्मविश्वास भी भरें, तो समाज को योग्य, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक मिलेंगे—और यही एक शिक्षक की सबसे बड़ी सफलता होगी।

गंगा और यमुना को लिविंग एंटिटी जैसा कानूनी दर्जा देना चाहिए

पर्यावरण की फिक्र
डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

गंगा और यमुना को 'लिविंग एंटिटी' या कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने का विचार केवल विधिक प्रश्न नहीं है, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और भविष्य के प्रति एक नैतिक परीक्षा भी है। दोनों नदियाँ न केवल पानी का प्रवाह हैं; वे हमारी स्मृतियों, उपासना, श्रम, अर्थव्यवस्था और जैव विविधता का आधार रही हैं। यदि हम वास्तव में इन नदियों को बचाना चाहते हैं, तो केवल नीतियाँ और परियोजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं होगा, हमें कानून के माध्यम से उनकी आवाज को सुनने और उनकी रक्षा के लिए स्थायी तंत्र गढ़ने की जरूरत है। न्यूजीलैंड की वांगानुई नदी एक आदर्श उदाहरण है। न्यूजीलैंड की वांगानुई नदी आदिवासी माओरी समाज के लिए माँ के समान है। 170 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद, वर्ष 2017 में वहाँ की संसद ने इस नदी को कानूनी दर्जा प्रदान किया। खुशी की बात है कि सिर्फ वांगानुई नहीं, अब तक कई देशों ने अपनी नदियों और जलस्रोतों को जीवित इकाई का क़ानूनी दर्जा देने की जिम्मेदारी निभाई है। कोलंबिया की अत्रातो नदी (2016) और अमेजन पारिस्थितिकी तंत्र (2018) को कानूनी अधिकार मिले। बांग्लादेश में 2019 में तुराग नदी और उसके साथ सभी नदियों को यह दर्जा दिया गया। कनाडा की मैग्पी नदी (2021) और अमेरिका की क्लैमथ नदी (स्थानीय आदिवासी कानून के तहत) को मान्यता मिली।हाल ही में इंग्लैंड में रिवर टेस्ट (2025) को प्रदूषण से बचाने के लिए यह दर्जा दिया गया। भारतमें भी 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों को क़ानूनी तौर पर जीवित इकाई घोषित किया। अदालत ने कहा कि ये नदियाँ हमारे लिए माँ के समान हैं और इन्हें व्यक्ति का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन दुःखद यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी। इसके फायदे और चुनौतियाँ क्या होंगी इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, कानूनी व्यक्तित्व देने के पीछे की तर्कशक्ति साफ है। जब किसी संस्थान या वस्तु को कानूनी व्यक्ति माना जाता है तो उसके लिए स्टैंडिंग, यानी अदालत में अपनी ओर से या उसके संरक्षक की ओर से मुकदमा दायर करने का अधिकार पैदा होता है। नदियों को यह स्तिथि मिलने पर कोई भी व्यक्ति, समुदाय या संरक्षक संस्था संविधान और पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकेगा। आज कई बार योजनाएँ और परियोजनाएँ नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती हैं, पर जवाबदेही अस्पष्ट रहती है—कानूनी व्यक्तित्व से जवाबदेही स्पष्ट और प्रभावी बन सकती है। दूसरी बड़ी वजह है पारिस्थितिकता का संरक्षण। नदियाँ न केवल मानव उपयोग की वस्तु हैं, बल्कि इकोसिस्टम का सक्रिय अंग हैं। मछलियाँ, नदी के किनारों के जीव, जलवायु पर उनका प्रभाव, और कृषि-वन्यजीवों के लिए उनका महत्व इन सबका अस्तित्व उनके समुचित प्रवाह, जलगुणवत्ता और तटवर्ती आवास पर निर्भर करता है। यदि नदी को कानूनी अधिकार दिया जाता है, तो न केवल प्रदूषण पर रोकथाम आसान होगी, बल्कि पुनर्स्थापना कार्यों की प्राथमिकता बनी रहेगी। नदियों के जल-गुणवत्ता मानदंडों का पालन, फ्लो रेकॉरिडोरों की रक्षा और जैविक विविधता की बहाली को कानूनी मान्यता मिलेगी। तीसरा पक्ष सामाजिक और सांस्कृतिक है। गंगा और यमुना करोड़ों लोगों की धार्मिक-आध्यात्मिक आस्था का हिस्सा रही हैं। उनके लिए ये न केवल जल स्रोत हैं बल्कि जीवन के सत्य और अनुष्ठानों का केंद्र हैं। कानूनी व्यक्तित्व देने का एक तर्क यह भी है कि यह उनकी सांस्कृतिक गरिमा को न्यायिक मान्यता देगा। इससे व्यवस्थागत स्तर पर उनके संरक्षण को वैधानिक महत्व मिलेगा और स्थानीय समुदायों की भागीदारी की प्रासंगिकता बढ़ेगी।

हालांकि, इसके साथ कई व्यावहारिक और वैचारिक चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं। पहला सवाल यह उठता है—किसे संरक्षक बनाया जाए? नदी को अधिकार देने का मतलब है कि उसका कोई प्रतिनिधि या संरक्षक होगा जो नदी के हित में निर्णय लेगा और अदालत में मुक़दमा दायर करेगा। यदि संरक्षक का चयन राजनीतिक, प्रशासनिक या व्यक्तिपरक हितों से प्रभावित हुआ तो वही संरक्षक नदी के वास्तविक हितों के खिलाफ काम कर सकता है। इसलिए संरक्षक तंत्र पारदर्शी, बहु-हितधारक और विज्ञान-आधारित होना चाहिए। जिसमें स्थानीय समुदाय, पारिस्थितिक विशेषज्ञ, जल विज्ञान के प्रतिनिधि और प्रशासनिक निगरानी सम्मिलित हों। दूसरी चुनौती है अधिकारों और दायरों के बीच सांकेतिक टकराव का। नदी का अधिकार मान लेना यह नहीं कि उसके पास असीमित अधिकार हों। नदियों के अधिकार और मानव उपयोग के अधिकारों के बीच संतुलन आवश्यक है। किसान, पीने का पानी, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, इन सबके अधिकारों को भी सुनिश्चित करना होगा। इसलिए कानूनी ढाँचे में स्पष्ट प्राथमिकी, सीमा और शर्तें रखनी चाहिए: किन परिस्थितियों में मानव उपयोग को प्राथमिकता मिलेगी, किन स्थितियों में नदी के अधिकार भारी पड़ेंगे, और किस तरह के परियोजनाओं पर प्रतिबंध या नियंत्रण होगा। तीसरी बड़ी कठिनाई शासन तंत्र की तैयारी है। कागज पर अधिकार देने से ज्यादा मायने यह रखता है कि धरातल पर क्या कार्रवाई होती है। नदियों की रक्षा के लिए पर्याप्त फंड, वैज्ञानिक निगरानी, जल-गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन, तटवर्ती संरक्षण परियोजनाएँ और जवाबदेही के तंत्र चाहिए। यदि कानूनी व्यक्तित्व से सिर्फ एक नया नाम जुड़ जाए पर अधिकारों की रक्षा के लिए संसाधन नहीं दिए गए तो वह नाम मात्र के अधिकार से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए कानूनी दर्जा एक प्रारंभ होना चाहिए—जिसे व्यावहारिक नीतियों, वित्तीय तंत्र और लोक भागीदारी के साथ जोड़ा जाए। यह भी जरूरी है कि नदियों के अधिकार देने की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और सहमति पर आधारित हो। गंगा और यमुना जिन राज्यों और समुदायों से होकर गुजरती हैं, उनकी जरूरतें और समझ अलग-अलग हैं। किसी भी निर्णय में स्थानीय जमीनी ज्ञान, मछुआरों और खेती-आधारित समुदायों की परम्परागत प्रथाएँ, तथा सांस्कृतिक मान्यताओं को सम्मिलित करना अनिवार्य है। केवल केबिनेट नोट या उच्च न्यायालय का आदेश ही पर्याप्त नहीं; व्यापक संवाद और सहभागिता से ही दीर्घकालिक सफलता संभव है। कानूनी दर्जा देने के बाद एक और संभावित लाभ यह होगा कि बड़े औद्योगिक और अवैध उपयोगों पर नियंत्रण सशक्त होगा। अति-निगमित और अनियंत्रित निकासी, untreated effluent का सागर में जाना और नदी के तटों पर अतिक्रमण—इन सब पर इंगित करने और रोक लगाने के लिए सशक्त वैधानिक औजार मिलेंगे। पर सावधानी यह कि नियम लागू करना मनमाना नहीं होना चाहिए; नीति-निर्माण में तथ्यात्मक आकलन, पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभावों का संतुलित मूल्यांकन और वैकल्पिक समाधान तलाशना साथ होना चाहिए। अंततः निर्णय केवल कानूनी दर्जे का नहीं होगा, यह राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का भी परीक्षण होगा। यदि सरकारें, न्यायपालिका और नागरिक समाज इसे केवल प्रतीकात्मक कदम मानकर लागू करती हैं तो लाभ सीमित रहेगा। पर अगर इसे एक व्यापक, विज्ञान-आधारित और समुदाय-संचालित आंदोलन के रूप में लिया जाए तो यह हमारी नदियों को पुनर्जीवित करने का बहु-निर्माणकारी अवसर हो सकता है। निष्कर्ष यह है कि गंगा और यमुना को 'लिविंग एंटिटी' का दर्जा देना एक साहसिक और आवश्यक विचार है, पर इसे विस्तारपूर्वक, सावधानी से और धरातलीय प्रतिबद्धताओं के साथ लागू करना होगा। हमें कानून को एक औजार के रूप में प्रयोग करना चाहिए जिससे पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक अधिकार और आर्थिक उपयोग के बीच संतुलन बनाया जा सके।

कलम के सिपाही

राजेश दुबेः मिजाज से राजा भी और रंक भी

-राघवेन्द्र सिंह

राजेश दुबे पत्रकारिता में एक ऐसा नाम जो मिजाज से राजा भी और रंक भी, सिपाही भी और सेनापति भी, जो रिपोर्टर भी और सम्पादक भी, व्यवहार में बच्चों जैसी सरलता भी और वरिष्ठता भी। पल में तोला, पल में माशा होने वाले राजेश जी के साथ मैंने 1990 के दशक में दैनिक जागरण में साथ-साथ रिपोर्टिंग की। स्वभाव में उदार, मिलनसार, यायावार, मनमौजी और मेहनतकशी मानो कूट-कूट कर भरी थी। कुल मिलाकर खबरों के मामले में उन्हें वन-मेन आर्मी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पत्रकारिता में सिद्धान्तों को लेकर सजग रहने के कारण जब-जब नौकरी छोड़ने की नौबत आई तो वे किसी से पीछे नहीं रहे। 1992 में राजेश दुबे सहित हम पाँच पत्रकारों ने एक अखबार से इसलिए नौकरी छोड़ दी थी कि प्रबन्धन की तरफ सिर्फ यह संकेत किए गए थे कि कुछ सरकारी महकमों से मिले विज्ञापनों के बिल लम्बित हैं उनके भुगतान करने में सम्बन्धित बीट के रिपोर्टर अपने रसूख का इस्तेमाल करें। इस तरह के इरादों की आहट मिलते ही नौकरी छोड़ एडिटर स्ट्रीट में जा खड़े हुए। अब की बात और है, सम्पादक तक विज्ञापन लाने से लेकर न्यूज मैनेजमेंट करने में सिर से पैर तक सने हैं। तब पत्रकारिता में दीक्षा ही मजलूमों की आवाज बनने की होती थी। कुछ ने उसे ही ओढ़ा और बिछाया। राजेश जी उन चुनिन्दा में से एक थे।

दैनिक जागरण में जब वे निगम-मण्डलों की रिपोर्टिंग करते थे तब कई बार खबरों की कमी का संकट होने पर वरिष्ठ साथी एक-एक पेज का मेटर तैयार करने के लिए राजेश की चिरौरी किया करते थे। स्वभाव से सरल राजेश थोड़ी ना नुकर के बाद अक्सर मेटर तैयार करने के लिए राजी हो जाते थे। इसके बाद पुराने सन्दर्भ और ताजा घटनाक्रमों को जोड वे एक-एक पेज की पठनीय सामग्री तैयार कर डालते थे। उस समय कम्प्यूटर तो थे नहीं, सिर झुकाए हाथ से पेज दर पेज घन्टों की लिखा पढी के बाद प्रेस के बाहर गुमठी पर चाय की चुस्कियों के साथ वे साथियों के साथ थकान दूर करते दिख जाया करते थे। पूछने पर तो वे कहते आजकल नौकरी संकट में है इसलिए खबरों की बेगारी भी करनी पड़ती है। निगम-मण्डल की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ थी। लेकिन मजाल है कि कभी उसका लाभ खुद के लिए लिया हो। कुछ समझदार कहा करते थे अपने और बच्चों के भविष्य के लिए अपने सम्बन्धों का उपयोग कर लें मगर उनका कहना था जिस दिन ऐसा करना होगा वे प्रेस काम्पलेक्स में कोई गुमठी लगाना पसन्द करेंगे। वे जो कहते थे, उसे जीते थे। जैसे थे, वैसे दिखते भी थे। दरअसल वे सिद्धान्तों, संस्कारों, नैतिक मूल्यों और मजलूमों और बेबसों की आवाज बनने वाली पत्रकारिता में दीक्षित हुए थे। दीक्षित तो अनेक हुए मगर राजेश ने अपनी ईमानदारी से उन राहों को रोशन भी किया। खुद की जिन्दगी की कीमत पर वे अपने और अपनों को छोड़, सबके लिए जिए। मिशन की पत्रकारिता में संस्कारित राजेश धन्धे की पत्रकारिता के फ्रेम में फिट नहीं हो पाए। उनके असमय चले जाने से कुल मिलाकर पत्रकारिता ने अच्छा पत्रकार और साथियों ने सच्चा मित्र खो दिया। राजेश दुबे का निधन 13 मार्च 2014 को हुआ।

89वें लेवल-ई मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमः वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल एम्स भोपाल पहुँचा

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से आए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। यह प्रतिनिधिमंडल 89वें लेवल-ई मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आया था, जिसका आयोजन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत संविधान प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान द्वारा किया गया था। इस प्रतिनिधिमंडल में अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल थे। ये अधिकारी स्वास्थ्य, रेलवे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्व, वस्त्र, प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास, उच्च शिक्षा, युवा मामले एवं खेल, संस्कृति, गृह मंत्रालय, आयुष, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, आवासन एवं शहरी कार्य, राजस्व विभाग भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, जल शक्ति, कृषि, जनजातीय कार्य और श्रम मंत्रालय जैसे अनेक मंत्रालयों से आए थे। प्रतिनिधिमंडल ने एम्स भोपाल की स्वास्थ्य सेवाओं की विविधता और गुणवत्ता की सराहना की। उन्होंने प्राथमिक देखभाल से लेकर उन्नत अंग प्रत्यारोपण तक की सेवाओं को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। साथ ही, एम्स भोपाल की रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण, पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था और स्वच्छ, हरा-भरा तथा पर्यावरण के अनुकूल परिसर की विशेष प्रशंसा की। इस भ्रमण का समन्वय प्रतिनिधियों की ओर से दीपक कुमार बिष्ट, पाठ्यक्रम समन्वयक और सुनील कुमार, अवर सचिव, राजस्व मंत्रालय ने किया।

इस अवसर पर एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. मधबानंद कर ने प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए संस्थान की मूल भावना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एम्स भोपाल का लक्ष्य उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान को बढ़ावा देने और विशेषकर जरूरतमंद समुदायों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने का है। एम्स भोपाल के कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक ने प्रतिनिधिमंडल को संस्थान की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एम्स भोपाल में प्रतिदिन औसतन 6,500 से अधिक मरीज उपचार हेतु पहुँचते हैं और वर्ष 2025 में अब तक 14 लाख से अधिक रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएँ दी गई हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि एम्स भोपाल ने रोगी देखभाल में डिजिटल एकीकरण और आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग शुरू किया है, जिससे मरीजों को और बेहतर सुविधा मिल रही है। डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने अतिथियों का औपचारिक स्वागत किया और पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय किया। इस अवसर पर उपनिदेशक (प्रशासन) संदेश जैन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। यह अवसर न केवल एम्स भोपाल के लिए सम्मानजनक रहा, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि यहाँ दी जाने वाली सेवाएँ और नवाचार पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में देखे जा रहे हैं। आम नागरिकों के लिए यह सुखद संदेश है कि मध्य भारत में ही उन्हें विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध हो रही हैं।

गुलाबंगज पुलिस ने नाबालिग बालिका को सकुशल परिजनों को किया सुपुर्द

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। थाना गुलाबगंज क्षेत्र से 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 137/25 धारा 137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। विदिशा जिले में अपहृत बालक/बालिकाओं एवं गुम इंसान की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह के मार्गदर्शन में लगातार विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 04.09.2025 को थाना गुलाबगंज पुलिस ने बालिका को बासौदा से सकुशल दस्तयाब किया। पुलिस टीम ने सूचनातंत्र एवं विवेकपूर्ण कार्यवाही करते हुए आरोपी राजाबाबू पिता शंकर सिंह आदिवासी (20 वर्ष), निवासी दफरियायी को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया, जहाँ से उसे जेल भेजा गया। दस्तयाब की गई बालिका को आवश्यक कार्यवाही उपरांत सकुशल उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। इस सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहर सिंह मंडेलिया, सउनि प्रहलाद सिंह रघुवंशी, प्रआर संजय यादव, आर. आशीष कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विदिशा पुलिस अब तक 269 से अधिक गुमशुदा/अपहृत बालक-बालिकाओं को सकुशल परिजनों से मिलवा चुकी है।

सतपुड़ा गौ अभ्यारण्य को हटाने 5 गांव के ग्रामीणों ने वन मण्डल अधिकारी को पत्र लिखा

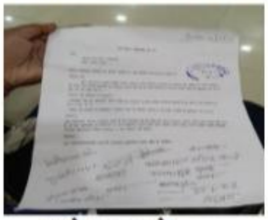

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। दिनांक 4 सितंबर को ग्राम कपासी उसकल्ली बरूडघाट जिनवानी व जोगीखेड़ा के ग्रामीणों द्वारा वन मण्डल हरदा को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने नेशनल हाईवे पर स्थित वन भूमि पर संचालित सतपुड़ा गौ अभ्यारण्य को हटाने की मांग रखी है। ग्रामवासियों ने लिखा है कि उक्त गौशाला से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। यहां का गौवंश खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है और उक्त भूमि पर संचालित गौशाला के कारण यहां के बहुकीमती करोड़ों के सागौन के वृक्ष भी सूख रहे हैं। ग्रामवासियों ने अनुरोध किया है कि 2 दिन के अंदर तत्काल उक्त गौशाला को हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ग्रामवासी आसपास के ग्रामीणों के साथ मिलकर पांचवें दिन रोड़ चक्का जाम करके धरना प्रदर्शन करेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन व वन विभाग की होगी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)